IJASRM
International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Special Issue 5, April 2019
www.ijasrm.com
ISSN 2455-6378

ग्रामीण आर्थिक विकास में सरकारी योजनाओं की भूमिका

डॉ. भावना ठाकुर
सह-प्राध्यापक (राजनीति षास्त्र)
शासकीय महाविद्यालय रेहटी

भारत गॉवों का देष है, और इसकी आत्मा गॉवों मे निवास करती है । ग्रामीण अंचलों का विकास किये बिना भारत विष्व आर्थिक विकास की दौड़ में अग्रणी नही हो सकता । इसी बात को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नियोजन प्रणाली के प्रारम्भ से ही भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास को सदैव प्राथमिकता प्रदान की गई । ग्रामीण विकास हेतु अनेक प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम का निर्माण कर उनका क्रियान्वयन किया गया ग्राम स्तर पर विकास कार्यक्रमों का संचालन, नैतृत्व एवं क्रियान्वयन ग्रामीणों के हाथों में सौंपा गया ग्रामीण क्षेत्र को दूरसंचार, बैंक, बीमा परिवहन, सिंचाई, आदि अनेक सुविधाओं से तेजी से जोड़ा गया जिससे ग्रामीण जन जीवन में एक नई क्रांति का स्त्रोत फूटा है , आर्थिक स्तर ऊपर उठा है । ग्रामीण क्षेत्रों मे लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, साख-सुविधाओं का विस्तार, निवेषकों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षिक करना आदि अनेक प्रयासों के फलस्वरूप भारत का ग्रामीण क्षेत्र आज गौरवपूर्ण रूप से २१वी शताब्दी में प्रवेष कर रहा है ।

भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है । यह अपने अन्दर सम्पूर्ण ग्रामीण इतिहास को समेटे एवं संजोये हुए है । भारत के गांवों का अलग-अलग राजाओं ने, राजनीतियों एवं शासकों ने अपने-अपने विवके, इच्छा एवं स्वार्थ से दोहन किया, कुछ राजा-महाराओं ने ग्रामीण विकास हेतु निःस्वार्थ प्रयास किये तथा कुछ ने अपने स्वार्थ सिद्धों हेतु इस ओर कुछ प्रयास किये किएं स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण विकास की ओर शासक वर्ग का ध्यान अपनी स्वार्थ प्रवृत्ति की पूति हेतु ही गया था ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण विकास एवं किसानों के हितों के लिए ठोस प्रयास किये गये। अनेक राज्यों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया पं० जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को नव-जीवन दिया सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को तेजी से अपनाया गया, गॉवों मे विद्युत, जल, षिक्षा, स्वास्थ्य आवास तथा ग्रामीण औद्योगीकरण सहित अनेक पिरयोजनाएं बनाई गई । गॉवों के विकास के लिए सरकार द्वारा बड़ी संख्या में अनेक परियोजनाएं एवं कार्यक्रम अपनाये गये जिनमें प्रमुख है - सामुदायिक विकास परियोजना (१९५२) राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (१९५३) सादी एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम (१९५७), ग्रामीण आवास योजना (१९५७), बहुउद्देष्यीय अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड कार्यक्रम (१९५७) पकेज कार्यक्रम (१९६०), गहन जिला कृषि कार्यक्रम (१९६०), व्यवहारिक आहार कार्यक्रम (१९६२) गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (१९६६) कृषक प्रषिक्षण एवं षिक्षा कार्यक्रम (१९६६) ग्रामीण जनषक्ति कार्यक्रम (१९६९), सूखा पीड़ित कार्यक्रम (१९७०), ग्रामीण रोजगार नगदी योजना (१९७१), ग्रामीण रोजगार नगदी योजना (१९७१), जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम (१९७२) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (१९७२) न्यूनतम आवष्यकता कार्यक्रम (१९७२) बीस सूत्रीय कार्यक्रम (१९७७) काम के बदले अराज कार्यक्रम (१९७७) सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम (१९७९) स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवा प्रषिक्षण कार्यक्रम ट्रायसेम (१९७९) राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम (१९८०), नया बीस सूत्री कार्यक्रम (१९८२) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (१९८३) समन्वित विकास योजना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना (१९८५-९०) की अवधि में चलाये गये । (१९९१-९२) में राजीव गांधी पेयजल मिषन आदि ।

ग्रामों को स्वाबलम्बी बनाने में सामुदायिक विकास परियोजनाओं की विषेष भूमि का रही है । इस परियोजना के मुख्य उद्दष्य थे ग्रामीण जनता में प्रगतिषील दृष्टिकोण का विकास करना, सहकारी ढग से काम करने की आदत उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि करना, गॉवों में षिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कुटीर एवं ग्रामीण उद्यागों का विकास, भूमि सुधार, सड़क निमाण आदि ।

कृषि उत्पादों को एक बाजार से दूरसरे बाजार तक पहुॅचाने, मंडी के अनेक शुल्कों से उत्पादकों को बचाने और उचित मूल्यों पर उपभाक्ता के लिए कृषि

वस्तुओं को मुहैया कराने के लिए सरकार ने ऑनलाईन मंच पर राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है । ताकि किसान किसी भी मंडी में अपनी पैदावार बेच सकें ग्रामीण विकास मंत्रालय देष के प्रत्येक गॉव में ऐसे सार्वजनिक और सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित कर रहा है, जहॉ कम्प्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलबध है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांवों की तस्वीर बदल कर रख दी है । गॉवों मे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, षिक्षा, संचार, रोजगार आदि के साधन बंद रहे है ।

जिस अंदाज से भारत के गॉवों मे मोबाईल फोनो और इंटरनेट का प्रयोग करने वालो की संख्या बढ़ रही है उससे संकेत मिलते है, कि ग्रामीण भारत में दूर संचार क्रांति की संभावना महज एक संभावना मात्र नही है । भारत के गॉवों मे मोबाईल अपभाक्ताओं की संख्या ४० करोड़ का ऑकड़ा छूने जा रही है । मोबाईल क्रांति के आगमन या उसकी आहट ने गॉवों मे दूरसंचार तकनीक के इर्द-गिर्द उद्यमिता और नवाचार तकनीक को भी प्रोत्साहित किया है । सूचना तकनीकी के प्रसार से गॉवों मे उद्यमिता का नया माहौल बना है । कृषि बाजार के लिए ई-प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है । सरकार की नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नही है । उम्मीद जताई जा रही है, कि यह फसल बीमा किसानों का भाग्य बदल देगी सरकार की कम प्रीमियम, बड़े बीमा वाली यह योजना किसानो की क्रय शान्ति में इजाफा करेगी प्राकृतिक आपदा में नष्ट होने वाली फसलों का १०० फीसदी मुआवजा मिलेगा योजना में टेक्नॉलाजी का उपयोग किया जायेगा ताकि फसल कटाई / नुकसान का आकलन शीघ्र और सही हो सके सौर ऊर्जा के विकास ने गॉव वासियों की जिन्दगी को आसान बना दिया ग्रामीण सड़कों का विस्तार होने से सामाजिक सास्कृतिक जीवन पर असर पड़ा, बालिकाओं की षिक्षा का प्रसार हुआ किसानों की वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की प्रवृत्ति बड़ी, डिजिटल इंडिया सरकार का एक ऐसा कदम है, जिसका न जिर्क सामाजिक पहलू है बल्कि व्यवसायिक पहलू भी है । इसके जरिये सरकार की मंषा गॉव के उस युवा को भी राष्ट्रीय मानचित्र पर ले आना है, जो अपने समान को पड़ोस वाले शहन तक भी ले जाने में असमर्थ था । मेक इन इंडिया की संकल्पना का आगाज इसी दिषा में उठाया गया एक कदम है । मेक इन इंडिया का अर्थ ऐसी वस्तुओं या उत्पादों से है । जिनका निर्माण भारत में किया गया हों । मौजूदा सम में भारत में बनी वस्तुओं की संख्या नगण्य है, जिसके कारण भारत को लोगें की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं का आयात दूसरे देषों से करना पड़ता है । मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत् सरकार घरेलू कम्पनियों द्वारा निर्मित उत्पादों को खरीदती है । और उनकी बिक्री बढ़ाने का प्रयास करती है । इस कार्यक्रम से ग्रामीण, कस्वाई एवं शहरी इलाकों में कुटीर उद्योगों का विकास होगा और लोगो को रोजगार मिलेगा ।

वर्तमान में ग्रामीण विकास के लिए जो भी कदम उठाये जा रहे है , वे सराहनीय है । किन्तु आज भी ग्रामीण भारत को अनेक जटिल समस्याओं ने चारो ओर से घेर रखा है । जिनके समाधान के लिए सरकार को एक निष्चित रूपरेखा बनाने की जरूरत है । ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने व महत्वपूर्ण और आकर्षक क्षेत्र होने के बावजूद कृषि क्षेत्र से लोगों का पलायन जारी है। शहरीकरण की प्रवृत्ति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति उदासीनता पैदा की है । संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र विगत कई दषक से महज कच्चे माल के स्त्रोत बनकर रह गये है । आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि नवीनतकनीकों के इस्तेमाल के बावजूद अनेक संकटों का सामना कर रही है । आजादी के इतने वर्षो में ग्रामीण अंचल की प्रगति की दिषा में भारत ने काफी लम्बा सफर तय कर लिया है । परन्तु इस लम्बे सफर मे जो सफलताएं मिली है । उन पर संतोष ही किया जा सकता है । गर्व नही / ग्रामीण विकास की गति तीव्र करने के लिए यह आवष्यक है कि ग्रामवासियों की क्षमताओं को जाग्रत कर उनका भरपूर सहयोग भी इस कार्य में लिया जाये ।

विगत वर्षो में ग्रामीण विकास हेतु अनेक प्रयास हुए है, परन्तु इन प्रासों का प्रभाव जितना अधिक मात्रात्मक रूप में पड़ा है, उतना सुधार गुणात्मक रूप में देखने कों नही मिला है । इस दिषा में नावार्ड तथा ग्रामीण बैंकों की भूमिका अहम हो जाती है । ग्रामीण क्षेत्रों में लाख-निर्माण, प्रचार-प्रसार तकनीकी ज्ञान, कृषि गुणवत्ता जागरूकता आदि महत्वपूर्ण जानकारी ग्रामीणों को दी जाने की आवष्यकता है ।

संदर्भः-

१. त्ततंस कमअमसवचउमदज दृ ळवचंस संस रंपदए डंदहंसकममच चनइसपबंजपवद. १६७७
२. त्ततंस कमअमसवचउमदज पद प्दकपं दृ क्तण् क्ण्ब्ण् चंदज अर्पूे ठींतजप चनइसपबंजपवदे छमू दृ कमसीप २००१ॅ

३. ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन - डॉ. पी.एन. पाण्डेय, रावत पब्लिकेषन्स जयपुर एवं नई दिल्ली ।
४. भारत में समन्वित ग्रामीण विकास एवं नियाजन- षिव-षंकर सिंह, राधा पब्लिकेषन्स, नई-दिल्ली
५. भारत में ग्रामीण विकास रणनीतियॉ एवं चुनौतियॉ- डॉ. सुरेन्द्र कटारिया, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर नई-दिल्ली
६. भारत में ग्रामीण समाज- डॉ.डी.एस.बघेल, कैलाष पुस्तक सदन भोपाल २०१६
७. ग्रामीण भारत समस्याएं एवं समाधान - डॉ. भूगालाल सुरेका, रूपा बुम्स प्रा०लि०जयपुर